International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2023; 5(2): 11-16
www.sociologyjournal.net
Received: 27-05-2023
Accepted: 01-07-2023

नैनिका कुमारी
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
नैनिका कुमारी
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

जी-20 संगठन की अध्यक्षता के माध्यम से भारत की वैश्विक राजनीति में भूमिका : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ

नैनिका कुमारी

DOI: https://doi.org/10.33545/26648679.2023.v5.i2a.53

सारांश

जी॰-20 ट्वेंटी का समूह (G-20) एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका , तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। जी॰-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में जी॰-20 की स्थापना की गई थी। वर्ष 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर इसे राज्य/सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अपग्रेड किया गया था, और वर्ष 2009 में, "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच" नामित किया गया था। इस शोध लेखन में जी॰-20 की संरचना और इसके कार्य पद्धति का विवेचना किया जाएगा।

जी-20 या ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी दुनिया की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसके नेता जी-20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने से जुड़ी योजना बनाने के लिए जुटते हैं। हर साल एक अलग जी॰-20 सदस्य राष्ट्र सम्मेलन का अध्यक्ष होता है और वही इसका एजेंडा भी तय करता है। वर्ष 2022 सम्मेलन का अध्यक्ष राष्ट्र इंडोनेशिया था जो बाली सम्मेलन के माध्यम से विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। इस सम्मेलन के दौरान दुनियाभर का नेता आपस में मुलाक़ात करते है और आपसी सहयोग से अन्य मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक जी॰-20 की अध्यक्षता करेगा है। प्रतिनिधिमंडलों के 43 प्रमुख जी॰-20 में अब तक के सबसे बड़े - अगले साल सितंबर में अंतिम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत जी॰-20 के माध्यम से वैश्विक मुद्दों और वैश्विक राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। इस शोध लेखन में भारत के समक्ष आने वाली वैश्विक चुनौतियों और इसके समाधान के उपाय का विश्लेषण होगा।

मूल शब्द : जी॰-20, वैश्विक राजनीति, वैश्विक मुद्दा, वितीय संकट, वैश्विक अर्थव्यवस्था, शिखर सम्मेलन, भू-राजनीति, सामरिक रणनीति

परिचय

वर्ष 1997 के एक बड़े एशियन वित्तीय संकट के बाद यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट होना चाहिये। इसके लिये इन देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स की एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट से बचा जा सके। इस उद्देश्य से जी॰-20 स्थापना 1999 में 7-देशों अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्राँस और इटली के विदेश मंत्रियों ने की थी। जी॰-20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना था। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इन देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की बैठक शुरू हुई। UN, IMF और विश्व बैंक के स्टाफ स्थायी होते हैं तथा इनके हेड क्वार्टर भी होते हैं, जबकि जी॰-20 का स्थायी स्टाफ नहीं होता है और न ही इसका हेड क्वार्टर ही है। यह सिर्फ एक फोरम मात्र है। इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय मार्केट, टैक्स, राजकोषीय नीति, आर्थिक भगोड़ों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा कृषि, रोज़गार तथा ऊर्जा संबंधी विषय भी शामिल हैं। पर्यावरण तथा सतत् विकास भी जी॰-20 में शामिल प्रमुख मुद्दे हैं। इस समूह का दुनिया की 85 प्रतिशत अर्थव्यवस्था और 75 प्रतिशत व्यापार पर नियंत्रण है। जी-20 दुनिया की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा तय करता है। जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के एजेंडे तय किए जाते हैं।

इसमें दुनिया की शीर्ष 19 अर्थव्यवस्था वाले देश और यूरोपीय संघ शामिल है। दुनियाभर का 85 प्रतिशत कारोबार जी-20 सदस्य देशों में ही होता है। वर्ष 1999 के एशियाई वित्तीय संकट के बाद बने इस संगठन का असली असर साल 2008 के बाद से दिखा जब आर्थिक मंदी के बाद सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सालाना सम्मेलन शुरू हुआ (विदेश मंत्रालय 2023 रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या-2) । शुरुआती सालों में जी-20 सम्मेलन से अंतरराष्ट्रीय कारोबार और आर्थिक लक्ष्यों को लेकर देशों के बीच समन्वय स्थापित हुआ और इसका असर भी दिखा। आगे चलकर जैसे-जैसे विश्व के मुद्दे बदले, जी-20 का एजेंडा भी बदलता गया और जलवायु परिवर्तन और 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद' जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने लगी। लेकिन जी-20 का एजेंडा व्यापक हुआ तो उसका असर भी कम। अब इसकी अध्यक्षता भारत के पास आ रही है, ऐसे में भारत के पास जी-20 को फिर से उसके आर्थिक लक्ष्यों की तरफ ले जाने का मौका होगा। भारत को इस 17वीं जी-20 सम्मेलन से क्या उम्मीद करनी चाहिए और 18वीं जी-20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने का ये मौका कितना महत्वपूर्ण है?

पिछले एक साल से भारत लगातार इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है कि जी-20 को किस तरफ ले जाना है और अलग-अलग मुद्दों को लेकर कैसे इस पर सहमति बनानी है। तो ये अच्छा अवसर होगा भारत के लिए दूसरे मुल्क़ के नेताओं से तालमेल बनाने का, उनको अगले साल भारत आने का निमंत्रण देने का और अपनी बात आगे रखने का। जी20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन अहम सत्रों में हिस्सा लिया था। ये हैं- खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजीटल ट्रांसफॉर्मेशन और स्वास्थ्य। भारतीय प्रधानमंत्री दुनियाभर के नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण कृषि और कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विशेषज्ञ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह मानते हैं कि ये भारत के पास वैश्विक मुद्दों को अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने का बड़ा मौका है। स्वर्ण सिंह कहते हैं, "भारत ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर एलायंस की बात हो या प्रधानमंत्री ने पिछले साल ग्लासगो में जो लाइफस्टाइल फॉर इंविरॉनमेंट की बात की थी, तो भारत को एक मौका मिलता है कि इतने बड़े मंच से अपनी बात कहने का और उसको एक दिशानिर्देश देने का।

भारत अब अगले 18वाँ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है और भारत ही इसका एजेंडा तय करेगा। भारत इस समय दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल है। भारत को अध्यक्षता मिलना ना सिर्फ़ बड़ी बात है बल्कि अपनी सोच को सामने रखने का बड़ा अवसर भी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत को इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़कर पहले अपने राष्ट्रहित को साधने का मौका मिलता है। इसके साथ-साथ पूरे विश्व में वित्तीय सोच और वित्तीय तालमेल को किस तरह से बनाकर जो बड़ी समस्याएं हैं विश्व की, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, ऊर्जा को लेकर हो, उनको कैसे सुलझाया जा सकता है, उस पर अपनी सोच सामने रखने और इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक दिशानिर्देश देने का अच्छा अवसर मिलता है भारत को (पंत 2023, पृष्ठ संख्या-4)।

जी॰-20 की संरचना और कार्य पद्धति

ट्वेंटी का समूह (G-20) एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश शामिल हैं - अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका , तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। जी॰-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में जी॰-20 की स्थापना की गई थी। वर्ष 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनजर इसे राज्य/सरकार के प्रमुखों के स्तर पर अपग्रेड किया गया था, और वर्ष 2009 में, "अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच" नामित किया गया था। जी॰-20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक घूर्णन प्रेसीडेंसी के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है।

जी॰-20 प्रेसीडेंसी एक वर्ष के लिए जी॰-20 एजेंडा चलाती है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है। जी॰-20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं: फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक । वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा किया जाता है। दो ट्रैक के भीतर, विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ आमंत्रित/अतिथि देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। शेरपा ट्रैक से जी-20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं। शेरपा ट्रैक 13 वर्किंग ग्रुप्स, 2 इनिशिएटिव्स - रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग (RIIG) और जी॰-20 एम्पावर, और विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स के इनपुट की देखरेख करता है, जिनमें से सभी साल भर मिलते हैं और समानांतर में अपने इश्यू नोट्स और आउटकम दस्तावेज़ विकसित करते हैं (ऑबजर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-11)। इन ठोस चर्चाओं के बाद शेरपा बैठकों के लिए सर्वसम्मति-आधारित अनुशंसाएँ प्राप्त होती हैं। शेरपा-स्तरीय बैठकों का परिणाम दस्तावेज अंततः नेताओं की घोषणा का आधार बनता है, जिस पर अगले साल सितंबर में अंतिम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में सभी जी॰-20 सदस्य देशों के नेताओं द्वारा बहस और हस्ताक्षर (आम सहमति के बाद और अगर होगा) किया जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे एंगेजमेंट ग्रुप हैं जो जी॰-20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, थिंक टैंकों, महिलाओं, युवाओं, श्रम, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं । स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना पहली बार भारत के जी॰-20 प्रेसीडेंसी के तहत की जाएगी, जो ड्राइविंग इनोवेशन में स्टार्टअप्स की भूमिका को पहचानता है जो तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य का जवाब देता है । इन समूहों के साथ सक्रिय परामर्श भारत के "समावेशी महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख", जी॰-20 दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है, जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष बाली शिखर सम्मेलन में रेखांकित किया था।

जी॰-20 का मुख्य मुद्दा

जी॰-20 का 17वाँ शिखर सम्मेलन कई मायने में काफी खास था। इस सम्मेलन के दौरान इस समूह के नेताओं द्वारा 10 साल पहले अस्तित्व में आए जी॰-20 के कार्यों की समीक्षा के साथ ही आने वाले दशक की नई चुनौतियों से निपटने के तरीके और समाधान पर भी चर्चा की। हाल ही में जी॰-20 के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई जिसे इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली में 'रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर' विषय के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान जी॰-20 शिखर सम्मेलन में जुटे देशों के नेताओं द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था, श्रम बाज़ारों के भविष्य और लिंग समानता के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा इस बार के एजेंडे में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, डिजिटल अर्थव्यवस्था, विश्व व्यापार संगठन में सुधार,

वित्तीय विनियमन, कराधान और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं (पंत 2023, पृष्ठ संख्या-6) । इसके साथ ही सम्मेलन का मुख्य फोकस भविष्य के विकास के लिये आधारभूत संरचना और खाद्य सुरक्षा पर है। विश्व के प्रमुख व्यापार भागीदारों, विशेष रूप से चीन से आयात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया टैरिफ का मुद्दा भी चर्चा का विषय रहा। इस सम्मेलन में जोय बाइडन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों शामिल हुए।

अमेरिका ने हाल ही में चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का टैरिफ लगभग था जिसका चीन ने कड़ा विरोध किया था। चीन को उम्मीद है कि वह अमेरिका को टैरिफ कम करने के लिये मना लेगा। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर देगा, जबकि चीन चाहता है कि टैरिफ की यह दर अधिकतम 10 प्रतिशत रहे। वर्तमान समय में विश्व की बदलती परिस्थिति में खासकर वणिज्य को लेकर चीन और अमेरिका के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर सारी दुनिया की नज़र है कि क्या इससे आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। वर्ष 2008 में जब जी॰-20 के बारे में परिकल्पना की गई थी उस वक्त विश्व आर्थिक संकट से गुज़र रहा था क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब थी और उसे बेहतर बनाने के लिये जी॰-20 के सारे नेताओं ने जो प्रेमवर्क अपनाया उसमें 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर आल' मुख्य एजेंडा था (विदेश मंत्रालय रिपोर्ट 2023, पृष्ठ संख्या-7) । आज की तारीख में देखें तो चीन और अमेरिका के बीच विवाद चल रहा है और राष्ट्रपति जोय बाइडन ने कहा है कि वह अभी भी टैरिफ लगाएंगे, इस नज़रिये से भी यह सम्मेलन महत्त्वपूर्ण है।

जी॰-20 में भारत की भूमिका

भारत 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक जी॰-20 की अध्यक्षता कर रहा है। प्रतिनिधिमंडलों के 43 प्रमुख- जी॰-20 में अब तक के सबसे बड़े - अगले साल सितंबर में अंतिम नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों - केसरिया, सफेद और हरा और नीला से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह को कमल के साथ जोड़ता है, भारत का राष्ट्रीय फूल जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के लिए भारत के ग्रह-समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। जी॰-20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में "भारत" लिखा हुआ है।

भारत के जी॰-20 प्रेसीडेंसी का विषय - "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" - महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से, विषय सभी जीवन के मूल्य की पुष्टि करता है - मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव - और ग्रह पृथ्वी पर और व्यापक ब्रह्मांड में उनकी परस्पर संबद्धता (विदेश मंत्रालय रिपोर्ट 2023, पृष्ठ संख्या-9) । विषय व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास दोनों के स्तर पर इसके संबद्ध, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) को भी उजागर करता है, जिससे विश्व स्तर पर परिवर्तनकारी कार्रवाइयां होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक स्वच्छ, हरित और धुंधला भविष्य होता है।

भारत के लिए, जी॰-20 प्रेसीडेंसी "अमृतकाल" की शुरुआत का भी प्रतीक है, 15 अगस्त 2022 को इसकी स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 साल की अवधि, इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी तक, एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जिसके मूल में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण है। जी॰-20 द्वारा सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करने, बहु-विषयक अनुसंधान करने और आपदा जोखिम में कमी पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए भारत की अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक नया कार्य समूह स्थापित किया जाएगा (ऑबजर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन रिपोर्ट 2023, पृष्ठ संख्या-1) । भारत के विशेष आमंत्रित अतिथि देश बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात हैं।

जी॰-20 के आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन UN, IMF, विश्व बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD, AU चेयर, NEPAD चेयर, ASEAN चेयर, ADB, ISA और CDRI हैं। जी-20 की बैठकें केवल नई दिल्ली या अन्य महानगरों तक ही सीमित नहीं रहेंगी। "वसुधैव कुटुम्बकम'-"एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" की अपनी जी-20 अध्यक्षता की थीम से प्रेरणा लेते हुए, साथ ही साथ 'सभी सरकार' दृष्टिकोण के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से, भारत 32 अलग-अलग शहरों में 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। वर्कस्ट्रीम, और जी॰-20 प्रतिनिधियों और मेहमानों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करने और उन्हें एक अद्वितीय भारतीय अनुभव प्रदान करने का अवसर होगा (विदेश मंत्रालय रिपोर्ट 2023, पृष्ठ संख्या-4) । प्रेसीडेंसी जी॰-20 सचिवालय के लिए देश के नागरिकों को एक अनूठा अवसर प्रदान करने का एक मौका भी है। भारत की जी॰-20 कहानी का हिस्सा। भारतीय जी॰-20 प्रेसीडेंसी ने जी॰-20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रितों और अन्य लोगों के लिए एक साल के लंबे भारत अनुभव की भी योजना बनाई है।

जी॰-20 का नेतृत्व करने का अवसर ऐसे समय में आया है जब अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि COVID-19 महामारी ने जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों के तहत हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इस संबंध में, जलवायु परिवर्तन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है, जिसमें न केवल जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान दिया गया है, बल्कि दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए सिर्फ ऊर्जा संक्रमण सुनिश्चित करना भी शामिल है।

यह समझते हुए कि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उद्योग, समाज और क्षेत्रों में व्याप्त है, भारत दुनिया को LiFE (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) -एक व्यवहार-आधारित आंदोलन प्रदान करता है जो हमारे देश की समृद्ध, प्राचीन स्थायी परंपराओं से उपभोक्ताओं को आकर्षित करता है, और बारी-बारी से बाजार, पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को अपनाने के लिए (विदेश मंत्रालय रिपोर्ट 2023, पृष्ठ संख्या-10) । यह भारत के जी॰-20 विषय: 'वसुधैव कुटुम्बकम' या 'वन अर्थ' के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। एक परिवार। एक भविष्य।

सतत विकास के लिए एक त्वरित, लचीला और समावेशी विकास एक आधारशिला है। अपने जी॰-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत का लक्ष्य उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। इसमें वैश्विक व्यापार में एमएसएमई के एकीकरण में तेजी लाने, विकास के लिए व्यापार की भावना लाने, श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने और श्रम कल्याण को सुरक्षित करने, वैश्विक कौशल अंतर को दूर करने और समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली आदि का निर्माण करने की महत्वाकांक्षा शामिल है। भारत की जी॰-20 अध्यक्षता 2030 एजेंडा के महत्वपूर्ण मध्यबिंदु से टकराती है। इस प्रकार, भारत COVID-19 के हानिकारक प्रभाव को स्वीकार करता है, जिसने कार्रवाई के मौजूदा दशक को पुनर्प्राप्ति के दशक में बदल दिया। इस परिप्रेक्ष्य के अनुरूप, भारत सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में निर्धारित

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी-20 के प्रयासों को फिर से प्रतिबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।

जी॰-20 प्रेसीडेंसी के रूप में, भारत प्रौद्योगिकी के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में अपने विश्वास को आगे बढ़ा सकता है, और कृषि से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे, वित्तीय समावेशन और तकनीक-सक्षम विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक ज्ञान-साझाकरण की सुविधा प्रदान कर सकता है। भारत की जी॰-20 प्राथमिकता सुधारित बहुपक्षवाद के लिए दबाव जारी रखना होगा जो अधिक जवाबदेह, समावेशी न्यायसंगत, न्यायसंगत और प्रतिनिधि बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाता है जो 21 वीं सदी में चुनौतियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त है महिला सशक्तीकरण और प्रतिनिधित्व भारत के जी॰-20 विचार-विमर्श के मूल में होने के साथ, भारत समावेशी विकास और विकास को उजागर करने के लिए जी॰-20 मंच का उपयोग करने की उम्मीद करता है। इसमें एसडीजी के सामाजिक-आर्थिक विकास और उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को आगे लाने और अग्रणी पदों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है (रितिका 2023, पृष्ठ संख्या-2)।

भारत ने सांस्कृतिक पहलों की एक श्रृंखला के साथ अपने प्रेसीडेंसी कार्यकाल के एजेंडे को शुरू किया, जिसमें विभिन्न जनभागीदारी गतिविधियां, देश भर के 75 शैक्षणिक संस्थानों के साथ एक विशेष यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम, जी-20 लोगो और रंगों के साथ एएसआई के 100 स्मारकों को रोशन करना, और नागालैंड में होम्बिल उत्सव में जी॰-20 का प्रदर्शन। सैंड आर्टिस्ट श्री सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर भारत के जी॰-20 लोगो की सैंड आर्ट भी बनाई। साल भर चलने वाले कैलेंडर में कई अन्य कार्यक्रमों, युवा गतिविधियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों संबंधित शहर-स्थलों के स्थलों और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली साइट भ्रमण की भी योजना बनाई गई है (विदेश मंत्रालय रिपोर्ट 2023, पृष्ठ संख्या-3)।

भारत ने जी॰-20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है। यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापी राजनीतिक और आर्थिक संकटों की एक श्रृंखला का मुकाबला कर रही है. यह पेपर अर्थात आलेख उन कारकों के संगम का वर्णन करने से हुए शुरू होता है, जो एकजुट होकर भारत की अध्यक्षता में साझा व्यापार पर व्यावहारिक जुड़ाव को, विशेष रूप से बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मज़बूत करने में आगे बढ़ने का एक अवसर मुहैया करवाते हैं : इसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में दोषों के आसपास का उद्देश्य; वैश्विक संचालन अथवा शासन मंच के रूप में जी-20 के राजनीतिक वजन; और भारत की अपने पॉवर का इस्तेमाल करने की क्षमता शामिल हैं। यह आलेख तीन श्रेणियों के तहत किए जाने वाले व्यापार से संबंधित हस्तक्षेपों की बात करता हैं, जिन्हें भारत की जी॰-20 अध्यक्षता के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है: ऐसे हस्तक्षेप जो एक अधिक अनुमानित और स्थिर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को आगे बढ़ाता हैं; व्यावहारिक प्रतिबद्धता; और विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रीत हस्तक्षेप, जो भारत को उसे अपने घरेलू अनुभवों से हासिल हुए हैं (ऑबजर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन रिपोर्ट 2023, पृष्ठ संख्या-1)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन अवरोधों का सामना करता है जो जितने राजनीतिक है, उतने ही तकनीकी भी हैं। जी-20 की प्रणालीगत प्रासंगिकता इसके राजनीतिक और सहकर्मी-शिक्षण कार्यों को रेखांकित करती है। वह इस प्रणालीगत प्रासंगिकता का उपयोग बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में अधिक पूर्वानुमान, स्थिरता और विश्वास पैदा करने के संबंध में कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। जी-20 में दुनिया के औद्योगिक देश और उभरते बाज़ार शामिल हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है, जिसमें शामिल देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत और दुनिया की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा अपने पास रखते हैं।

उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों की चिंताओं और अपने स्वयं के हितों और विकसित होते घरेलू व्यापार परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के पास संयोजन क्षमता और इससे जुड़े विचार मौजूद है। ऐसे में उपरोक्त तीन कारक, भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिचालन स्थितियों पर आम सहमति को बढ़ावा देने, सामूहिक विचार के लिए अग्रिम ठोस व्यापार प्रतिबद्धताओं और अपने स्वयं के घरेलू अनुभव से दुनिया को सबक प्रदान करने का अधिकार प्रदान करते हैं। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत, यूनाइटेड किंगडम (यूके) से आगे निकल गया है. अन्य क्षेत्रों में मंदी के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। (भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के शब्दों में)।

एक उभरते बाज़ार और ''वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक स्तंभ'' के रूप में भारत की साख, इसकी क्षेत्रीय स्थिति और उभरते वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए, वह खुद को कूटनीतिक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों, दोनों की दृष्टि से एक वांछित राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक भागीदार के रूप में देख रहा है। एक मल्टी-अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी अर्थात बहु-संरेखण रणनीति के तहत पॉवर्स अर्थात शक्तियों और क्षेत्रों के साथ संबंधों को बनाने की कोशिश भारत को एक मजबूत संयोजन शक्ति प्रदान करती है, जो वर्तमान ख़राब अंतर्राष्ट्रीय माहौल में उपयोगी साबित होगी. हालांकि इसके साथ ही इस तरह का 'ब्रीजिंग रोल' अर्थात ''सेतु भूमिका'। भारत के लिए विरोधाभासी रूप से बहुपक्षीय मंचों के समक्ष विवादास्पद मुद्दों को उठाने के झुकाव को सीमित भी कर सकती है।

फिर भी, तथ्य यह है कि ''अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए भारत अधिक से अधिक दिशाओं में पहुंच रहा है। इस प्रकार वह कठोर भू-राजनीतिक बायनेरिज़ अर्थात दोहरी साझेदारी के बाहर पार्टनरशिप अर्थात गठबंधन की तलाश कर रहा है। इसका मतलब है कि भारत आत्मविश्वास के साथ विकासशील दुनिया की आवाज और साझा हितों और आम प्राथमिकताओं को उठाने का दावा कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बाकी दुनिया के लिए ग्रोथ अर्थात विकास और डेवलपमेंट आउटकम्स् अर्थात विकास के परिणामों को निर्धारित नहीं करती है, वैश्विक दक्षिण का समर्थन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि इस पेपर के सेक्शन 1 में बताया गया है, यह बात व्यापार के क्षेत्र में भी लागू होती है।

वर्ष 2022 और वर्ष 2025 के बीच उभरते बाज़ारों और विकासशील देशों के लगातार प्रेसीडेंसी के अवसर का उपयोग भारत एक निरंतर व्यापार एजेंडा विकसित करने के लिए कर सकता है; विशेष रूप से भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) समूह उपयोगी साबित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपनाने का भारत का अनुभव उसे विशेष रूप से स्थानीयकरण और वैश्वीकरण के बीच आर्थिक सुरक्षा विचारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ बहस के संदर्भ में एक एजेंडा स्थापित करने में सहायक होगा : मजबूत और अधिक प्रतिस्पर्धी घरेलू क्षमता और बढ़ी हुई पहुंच और पैमाने के लिए विविध वैश्विक आर्थिक संबंधों के माध्यम से विकास के अपने घरेलू एजेंडे के साथ भारत को मिला नेतृत्व का अवसर आज अतीत में किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में बेहतर रूप से संरेखित है।

भले ही भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम है और वैश्विक

व्यापारिक आयात में उसकी 3 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी भी कमज़ोर बनी हुई है। दक्षिण कोरिया और मलेशिया जैसी छोटी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में जीवीसी के माध्यम से भारत की वैश्विक व्यापार भागीदारी भी कम ही है। 2030 तक भारत ने खुद के लिए 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का एक अल्पकालिक लक्ष्य तय किया है। जबकि वैश्विक निर्यात में वह 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी की उम्मीद लेकर चल रहा है। उसने 2047 तक वैश्विक निर्यात में 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही वह इस वक्त तक वैश्विक सेवा व्यापार में शीर्ष तीन में स्थान हासिल करना चाहता है। अब तक भारत की विकास गाथा में एक सक्षम नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में एक अधिक अनुमानित और स्थिर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए आम सहमति बनाना उसके अपने हित में ही होगा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जी20 की अध्यक्षता भारत को अपनी विदेश व्यापार नीति को अपनी एक्सर्टनल ट्रेड पोज़िशनिंग अर्थात बाहरी व्यापार स्थिति के साथ संरेखित करने का एक बाहरी प्रोत्साहन मुहैया करवाती है। ताकि वह एक विश्वसनीय व्यापार भागीदार के रूप में अपनी विश्वसनीयता को मजबूत कर सके इस वजह से वैश्विक स्तर पर प्रमुख व्यापार वार्तालापों का नेतृत्व करने की वैधता हासिल कर सकें। वास्तव में, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति को अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि उस वक़्त तक यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीति के तहत निर्धारित उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रणाली के अनुरूप, सुसंगत और अनुपालन करने वाले हैं।

निष्कर्ष

भारत ने संकेत दिए हैं कि जी-20 अध्यक्षता के दौरान वह विकासशील देशों की आवाज को मुखरता से उठाएगा। वह ग्लोबल गवर्नेंस के लिए समाधान सुझाने में सक्रिय रहेगा। डिजिटल और डाटा के मोर्चे पर अपनी महारथ से दुनिया की मदद करेगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान तलाशने पर काम करेगा। भारत ने इस सिलसिले में काम भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी और चीनी तकनीक पर आश्रित दुनिया को उसने विकल्प देने की पहल की है। भारत के सफल डिजिटल भुगतान यूपीआइ में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही स्वदेशी 5जी तकनीक भी कई देशों को लुभा रही है।

वास्तव में भारत जी-20 की अध्यक्षता को बहुत गंभीरता से ले रहा है और उसने अपना एजेंडा बनाकर उसे अमल में लाना भी आरंभ कर दिया है। इसके माध्यम से भारत अपने विकास की गाथा दुनिया को दिखाकर वैश्विक ढांचे में और ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा। एक ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था महत्वपूर्ण मुद्दों पर मात्र मूकदर्शक बनकर रह गई हो तो जी-20 जैसे संगठन की भूमिका और अहम हो जाती है। वर्तमान परिस्थितियों में भारत के रूप में उसे उचित और वास्तविक नेतृत्वकर्ता भी मिला है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की आहट से परेशान है, तब भारत दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 'अंधेरे में उम्मीद की एकमात्र किरण' करार दिया है।

वसुधैव कुटुंबकम् के माध्यम से भारत विश्व को आश्वस्त करना चाहता है कि वह केवल अपना ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की कामना करता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। कोविड महामारी के दौरान भारत का अनुकरणीय आचरण इस थीम के संदेश से पूरा न्याय करता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बनी हैं, उनमें चाहे पश्चिमी देश हों या उनका धुर विरोधी रूस और उनके टकराव से प्रभावित विकासशील देश, वे सभी भारत पर पूरा भरोसा करते हैं और इस समय यदि कोई देश दुनिया में स्थायित्व एवं शांति लाने में सबसे सार्थक भूमिका निभा सकता है तो वह भारत ही है।

वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बीच संपन्न हुई जी॰-20 समूह की शिखर बैठक से निकले नतीजे भारत के लिहाज़ से सकारात्मक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जोय बाइडन के संरक्षणवाद और अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर के अलावा आर्थिक प्रतिबंध, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, यूरोपीय संघ की मुश्किलें, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अशांति तथा गहराती शरणार्थी समस्या जैसी चुनौतियों के मद्देनज़र इस सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थीं। हालाँकि इसमें भाग ले रहे राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों द्वारा कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की गई है जिसके आधार पर तात्कालिक तौर पर किसी नतीजे पर पहुँचा जा सके किंतु जो समझौते हुए हैं तथा एकजुटता बढ़ी है, उससे भविष्य में बेहतरी की उम्मीदें ज़रूर बढ़ी हैं। अमेरिका और चीन ने कुछ समय के के लिये टैरिफ को लेकर प्रतिस्पर्द्धा को स्थगित कर दिया है, तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। दुनिया के प्रति-दिन बदलते माहौल में आर्थिक विकास के लिये विकासशील देशों के बीच आपसी संवाद और तालमेल बेहद अहम है। इस प्रकार तमाम देश आपसी सहयोग और समझदारी से न सिर्फ वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं बल्कि खुद को भी आर्थिक तौर पर मज़बूत बना सकते हैं।

संदर्भ सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (2023), जी॰-20 : कृषि वर्किंग ग्रूप, URL: https://agricoop.gov.in/awg-g20/
2. पंत, हर्ष वी॰ (2023), भारत और जी॰-20 : दिल्ली से बाहर कूटनीति, ऑबजर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://policycommons.net/artifacts/3412898/india-and-the-g-20/4212317/
3. पंत, हर्ष वी॰ (2022), भारत जी॰-20 की अध्यक्षता : एक सुनहरा अवसर, ऑबजर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन,
4. URL: https://policycommons.net/artifacts/3184268/indias-g-20-presidency-is-a-golden opportunity/3982864/
5. पंत, हर्ष वी॰ (2023), जी॰-20 की महत्ता, भारत भी तैयार है अपनी भूमिका निभाने में, ऑबजर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/hindi/research/increased-importance-of-g20-india-is-also-ready/
6. पासी, रितिका (2022), उद्देश्य, मंच और शक्ति : भारत की जी॰-20 की अध्यक्षता के वर्ष में व्यापारिक प्रगति, ऑबजर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन, URL: https://www.orfonline.org/hindi/research/purpose-platform-and-power-advancing-trade-under-indias-g20-presidency/
7. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (2022), जी॰-20 का अवलोकन, URL: https://moes.gov.in/g20-india-2023/moes-g20?language_content_entity=en
8. भारतीय विदेश मंत्रालय (2023), भारत और जी॰-20 प्रेसीडेंसी, URL: https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1882356
9. पंत, हर्ष वी॰ (2022), जी॰-20 : बहुपक्षीय संस्थान के लिए गमन, यूरोपियन यूनियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ सेक्यूरिटी स्टडीज़,
10. URL:https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/The_G20__a_pathway_to_effective_multilateralism.pdf

11. एशियन विकास बैंक (2023), भारत का जी॰-20 की अध्यक्षता : भारत का आर्थिक विकास, URL: https://www.adb.org/news/features/indias-g20-presidency-opportunity
12. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (2023), जी॰-20 की भारत द्वारा अध्यक्षता, URL: https://mea.gov.in/rajya-sabha.htm?dtl/36893/QUESTION_NO863_DETAILS_OF_INDIAS_PRESIDENCY_OF_G20
13. ऑबजर्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2023), भारत के जी॰-२० की अध्यक्षता के समक्ष पाँच चुनौतियाँ, URL: https://www.orfonline.org/hindi/research/five-challenges-before-indias-g20-presidency/